

धुरन्धर प्रसाद सिंह

बनाम

जय प्रकाश विश्वविद्यालय एवं अन्य।

24 जुलाई, 2001

[जी.बी. पटनायक और बी.एन. अग्रवाल, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 47-धारित दायरे और दायरे के तहत शक्तियों का प्रयोग प्रतिवादित डिक्री को रद्द किया जा सकता है यदि वह शुरू से ही शून्य और आमन्य है - लेकिन किसी पक्ष को पक्षकार बनाए बिना पारित की गई डिक्री शुरू से ही शून्य नहीं है जिससे उसकी बर्खास्तगी हो सके। ऐसी किसी डिक्री को उचित रूप से वाद दायर करके चुनौती दी जानी चाहिए।

आदेश 22 नियम 10-वाद का लंबित होना-हित का समनुदेशन-वाद जारी रखने की अनुमति-आयोजित: वाद जारी रखने के लिए अनुमति मांगने का प्रारंभिक कर्तव्य वादी पर है-लेकिन जिस व्यक्ति पर हित का समनुदेशन हुआ है, या कोई भी इच्छुक व्यक्ति, ऐसी अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है ताकि उसके हितों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके।

अपीलकर्ता-वादी ने यह घोषणा करने के लिए वाद दायर किया कि अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित आदेश अवैध था। वाद का एक पक्षीय फैसला सुनाया गया। अपीलकर्ता द्वारा दायर निष्पादन आवेदन में, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 के तहत इस आधार पर आपत्ति उठाई कि वाद

के लंबित रहने के दौरान विचाराधीन कॉलेज, जो कि प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय की घटक इकाई बन गया, को वाद में एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था और इसलिए, एक पक्षीय डिक्री निष्पादन योग्य नहीं थी। निष्पादन करने वाली अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण की अनुमति दे दी। इसलिए यह अपील

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि कॉलेज को प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए यह आदेश 22 नियम 10 सीपीसी के अर्थ के तहत वाद के लंबन काल में हित के समनुदेशन का मामला था; कि प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने आदेश 22 नियम 10 के तहत वाद जारी रखने के लिए अनुमति लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इसलिए, एकपक्षीय डिक्री निष्पादन योग्य थी।

प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी-वादी जो वाद चला रहा था, का यह कर्तव्य था कि प्रभावी प्रत्यर्थी राहत के लिए वह विश्वविद्यालय को आदेश 22, नियम 10 के तहत रिकॉर्ड पर लाए।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठे:-

1. क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 10 के तहत बताए गए वाद के लम्बन काल में हित के समनुदेशन के मामले में,

उत्तराधिकारी-हित को रिकॉर्ड पर लाए बिना पूर्ववर्ती-हित के खिलाफ डिक्री पारित की गई, डिक्री को अमान्य बना देगा और इसे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है जिसे पार्टी के रूप में संयोजित नहीं किया गया था?

2. क्या आदेश 22 नियम 10 के तहत न्यायालय की अनुमति के लिए आवेदन केवल उस व्यक्ति द्वारा पेश किया जाना आवश्यक है, जिस पर वाद के लंबित रहने के दौरान हित का समनुदेशन किया गया है, किसी और द्वारा नहीं?

अपील स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने माना:

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 के तहत शक्तियों का प्रयोग सूक्ष्म है और एक बहुत ही संकीर्ण निरीक्षण क्षेत्र में निहित है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निष्पादन न्यायालय डिक्री की निष्पादन क्षमता पर संहिता की धारा 47 के तहत आपत्ति की अनुमति दे सकता है यदि यह पाया जाता है कि डिक्री प्रारंभिक रूप से शून्य और अशक्त है, इस आधार के अलावा कि डिक्री निष्पादन में सक्षम नहीं है, क्योंकि कानून के तहत या तो इसे कानून के ऐसे प्रावधान की अनदेखी में पारित किया गया था या कानून पारित होने के बाद किसी कानून को अक्षम्य बनाकर प्रख्यापित किया गया था। मौजूदा मामले में, विश्वविद्यालय के खिलाफ वाद जारी

रखने के लिए अदालत की अनुमति मांगे बिना, और पक्षकार बनाए बिना, जिस पर मूल प्रतिवादी का हित स्थानान्तरित हुआ था उस कॉलेज के खिलाफ डिक्री पारित कर दी गई थी, जो प्रतिवादी था, इस तरह की चूक डिक्री को शुरू से ही रद्द नहीं कर देगी ताकि संहिता की धारा 47 के आवेदन को लागू किया जा सके और निष्पादन को खारिज किया जा सके। डिक्री की वैधता या अन्यथा को उचित रूप से वाद दायर करके या कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय से इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि मूल प्रतिवादी ने उपस्थिति के बाद वाद की कार्यवाही से खुद को अनुपस्थित कर लिया क्योंकि इसमें उसकी अब वाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी या जानबूझकर कार्यवाही में रुचि नहीं ली या विरोधी के साथ मिलीभगत की अथवा कानून के तहत स्वीकार्य किसी अन्य आधार पर।

मोती लाल बनाम करब-उद-दीन, (1898) 25 कैल 179; प्राणनाथ बनाम रूकीया बेगम, (1851-59) 7 एमआईए 323; श्रीमती सैला बाला दासी बनाम श्रीमती निर्मला सुंदरी दासी, एआईआर (1958) एससी 394; रिखु देव, चेला बावा हरजुग दास बनाम सोम दास, एआईआर (1975) एससी 2159; किरण सिंह बनाम चमन पासवान, एआईआर (1954) एससी 340; जुत्यावीरा मथाई बनाम. वर्की बनाम वर्की, एआईआर (1964) एससी 907; वासुदेव धनजी भाईमोदी बनाम राजाभाई अब्दुल रहमान, एआईआर (1970) एससी 1475; एवरेस्ट काॅयल कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम बिहार

राज्य, [1978] 1 एससीसी 12; हाजी एस.के. सुभान बनाम माधोराव, एआईआर (1962) एससी 1230 और विद्या सागर बनाम श्रीमती सुदेश कुमारी, एआईआर (1975) एससी 2295, संदर्भित।

दुरयप्पा बनाम फर्डिनेंड, (1967) 2 आल ईआर 152; इनरे मैकसी (अवयस्क)(1985) 1 एसी 528 और लोक अभियोजन निदेशक बनाम प्रमुख, (1959) एसी 83 और आर. वी. पैडिंगटन मूल्यांकन अधिकारी, (1965) 2 सभी ईआर 836, संदर्भित।

डी स्मिथ, वुल्फ और जोवेल: प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा, 5 वां संस्करण। पैरा 5-044 और क्लाइव लुईस: सार्वजनिक कानून में न्यायिक उपचार, पृ. 131, संदर्भित.

2.2. आदेश 22 नियम 10 सीपीसी की स्पष्ट भाषा यह नहीं बताती है कि अनुमति केवल उस व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है जिस पर हित का समनुदेशन हुआ है। इसमें बस यह कहा गया है कि वाद उस व्यक्ति द्वारा जारी रखा जा सकता है जिस पर ऐसा हित हस्तांतरित हुआ है और यह उस मामले में लागू होता है जहां वादी का हित हस्तांतरित हुआ है। इसी तरह, ऐसे मामले में जहां प्रतिवादी का हित हस्तांतरित हो गया है, वाद ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी रखा जा सकता है, जिस पर हित का समनुदेशन हुआ है, लेकिन किसी भी स्थिति में, वाद के लंबन काल में उन

व्यक्तियों के खिलाफ वाद जारी रखा जा सकता है, जिन पर हित का समनुदेशन हुआ है, अदालत की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि यह निर्धारित किया जाता है कि अनुमति केवल उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिस पर वाद के पक्षकार का हित लंबित रहने के दौरान हस्तांतरित हुआ है, तो बेतुके परिणाम हो सकते हैं क्योंकि ऐसे पक्ष को वाद के बारे में पता नहीं होगा और परिणामस्वरूप यह संभव नहीं होगा कि वह अनुमति के लिए आवेदन कर सके और यदि उस पर कोई कर्तव्य डाला जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुमति के लिए आवेदन न करने की स्थिति में भी वह डिक्री से बंधा होगा। विवेक के एक नियम के रूप में, प्रारंभिक कर्तव्य वादी पर है कि वह अनुमति के लिए आवेदन करे यदि हस्तांतरण का तथ्य उसकी जानकारी में था या उचित परिश्रम के साथ उसे पता चल सकता था। वह व्यक्ति जिस पर हित हस्तांतरित हो गया है, वह भी ऐसी अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है ताकि उसके हित को मूल पक्ष के रूप में उचित रूप से दर्शाया जा सके यदि मूल पक्षकार सामान्य तौर पर, जो स्वाभाविक है, किसी अन्य को हित हस्तांतरित होने के कारण विवाद के विषय-वस्तु में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है या दूसरे पक्ष के साथ मिलीभगत करके, उसमें रुचि नहीं लेता। अनुमति के लिए प्रार्थना न केवल उस व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर हित हस्तांतरित हुआ है, बल्कि वादी या किसी अन्य पक्ष या इच्छुक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है।

सिविल अपील की अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4481/2001

सी.आर. संख्या 98/1998 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.7.99 से।

अपीलकर्ता की ओर से पी.एस मिश्रा, एस. चंद्र शेखर, विष्णु शर्मा और राजेश प्रसाद सिंह।

प्रत्यर्थागण की ओर से राजू रामचन्द्रन, रुद्रेश्वर सिंह, तपेश सिंह, शिशिर पिनाक्री और आर.पी. वाधवानी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

बी.एन. अग्रवाल, जे. अनुमति स्वीकृत।

इस अपील में डिक्री 'धारक-अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी गई है, निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत 1977 के टाइटल सूट नंबर 115 में पारित डिक्री की निष्पादनशीलता की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है') को रद्द कर दिया गया और आपत्ति की अनुमति दी गई।

वादी-अपीलकर्ता ने यह घोषित करने के लिए वाद दायर किया कि प्रत्यर्था संख्या 2 (प्रतिवादी संख्या 3) जो गवर्निंग बॉडी, गंगा सिंह कॉलेज

के सचिव थे, द्वारा वादी की सेवाओं को समाप्त करने का दिनांक 11 अक्टूबर 1977 का आदेश अवैध था। वाद-पत्र में प्रकट किये गये वादी के मामले के अनुसार, उन्हें 8.1.1977 को कॉलेज के प्राचार्य द्वारा उक्त कॉलेज, जो कि बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध था, में रूटीन-सह-परीक्षा लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में अडहॉक गर्वनिंग बाँडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। नियमित शासी निकाय के गठन के बाद, प्रतिवादी नंबर 2 ने बिहार विश्वविद्यालय के नियमों के उल्लंघन में वादी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित किया, जिसके कारण वर्तमान वाद दायर करना आवश्यक हो गया। उक्त वाद में, कॉलेज की गवर्निंग बाँडी, जो कि प्रतिवादी नंबर 1 थी, उपस्थित हुई, लेकिन कोई जवाब दावा दायर नहीं किया गया व प्रतिवादी अनुपस्थित रहा और वाद एकपक्षीय सुनवाई के लिए तय किया गया, जिसमें एकपक्षीय आदेश दिया गया और प्रतिवादियों को स्थायी रूप से सेवा समाप्ति के आदेश को प्रभावी करने से रोका गया। चूँकि निर्णित ऋणी ने डिक्री में निहित निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया, अपीलकर्ता ने निष्पादन लगाया। उक्त निष्पादन मामले में, कॉलेज के प्राचार्य के साथ-साथ बिहार विश्वविद्यालय की ओर से संहिता की धारा 47 के तहत एक आपत्ति दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति जताई गई कि दौराने दावा 1 अक्टूबर, 1980 को विचाराधीन कॉलेज बिहार विश्वविद्यालय की घटक



इकाई बन गया और तत्कालीन शासी निकाय का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया और इस तथ्य को छिपाकर तत्कालीन प्रबंधन के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली गई। परिणामस्वरूप इसके खिलाफ डिक्री निष्पादन योग्य नहीं थी। जैसा कि बाद में निष्पादन मामले के लंबित रहने के दौरान, जय प्रकाश विश्वविद्यालय का गठन किया गया और उसके बाद विचाराधीन कॉलेज उक्त विश्वविद्यालय की एक घटक इकाई बन गया, उसने भी डिक्री की निष्पादन क्षमता पर भी इसी तरह की आपत्ति दर्ज की।

कार्यकारी अदालत ने आपत्ति की अनुमति दी और उसके बाद जब मामले को पुनरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय में ले जाया गया, तो पक्षों को साक्ष्य पेश करने का अवसर देने के बाद आपत्ति को नए सिरे से निपटाने के लिए मामले को कार्यकारी अदालत को भेज दिया गया। रिमांड के बाद पक्षों ने अपने संबंधित मामलों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए और निष्पादन न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22 सितंबर, 1997 द्वारा संहिता की धारा 47 के तहत आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसके आदेश के खिलाफ जब उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था, तो उसे अनुमति दी गई थी। निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और संहिता की धारा 47 के तहत आपत्ति की अनुमति दी गई। अतः यह अपील विशेष अनुमति द्वारा।

अपील के समर्थन में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभा शंकर मिश्रा ने कहा कि यद्यपि विचाराधीन कॉलेज को बिहार विश्वविद्यालय ने अपनी सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ अपनी घटक इकाई के रूप में ले लिया था और यह संहिता के आदेश 22 नियम 10 के अर्थ के अंतर्गत वाद के लंबित रहने के दौरान हितों के हस्तांतरण का एक मामला था, उच्च न्यायालय को यह मानना उचित नहीं था कि डिक्री को विश्वविद्यालय के खिलाफ इस आधार पर निष्पादित नहीं किया जा सकता है कि उसे मामले में पार्टी नहीं बनाया गया था। मामला यह है कि डिक्री तत्कालीन प्रबंधन के खिलाफ पारित की जा सकती थी और विश्वविद्यालय इससे बंधा हुआ था क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया था ताकि इसे जारी रखने के लिए अनुमति मांगी जा सके, जो अकेले इसके लिए हकदार था। दूसरी ओर, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि संहिता के आदेश 22 नियम 10 के तहत, यह वादी का कर्तव्य था कि अदालत की अनुमति मांगकर यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय जो एक आवश्यक पक्षकार था को रिकॉर्ड पर लाकर प्रभावी राहत प्राप्त करे। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पिछले प्रबंधन के खिलाफ पारित डिक्री, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, एक मृत व्यक्ति के खिलाफ उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाए बिना पारित डिक्री के समान है, जो

कि अमान्य है। इस प्रकार, प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को देखते हुए, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:-

1. क्या संहिता के आदेश 22 नियम 10 के तहत किसी वाद के लंबित रहने के दौरान हित के हस्तांतरण के मामले में, हित के उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पर लाए बिना पूर्ववर्ती-हित के खिलाफ पारित डिक्री डिक्री को अमान्य बना देगी और इसे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है जिसे पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था?

2. क्या आदेश 22 नियम 10 के तहत न्यायालय की अनुमति के लिए आवेदन कानून के तहत केवल उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना आवश्यक है, जिस पर वाद के लंबित रहने के दौरान ब्याज हस्तांतरित किया गया है, किसी और द्वारा नहीं?

इसमें शामिल बिंदुओं की सराहना करने के लिए, संहिता के आदेश 22, नियम 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो किसी वाद में किसी पक्ष की मृत्यु पर हित के हस्तांतरण के मामले में प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। इन नियमों के तहत, यदि किसी पक्ष की मृत्यु हो जाती है और वाद करने का अधिकार जीवित रहता है, तो उस संबंध में किए गए आवेदन पर वाद को आगे बढ़ाने के लिए मृत पक्ष के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है, लेकिन यदि ऐसा कोई

आवेदन कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं किया जाता है तो जहां तक मृतक पक्ष का संबंध है, वाद समाप्त हो जाएगा। नियम 7 विवाह पर पति में हित पैदा करने के मामले से संबंधित है और नियम 8 वादी के दिवालिया होने पर समनुदेशन के मामले से संबंधित है। नियम 10 पूर्वगामी नियमों में निर्दिष्ट मामलों के अलावा किसी वाद के लंबित रहने के दौरान हित के समनुदेशन, सृजन और हस्तांतरण के मामलों का प्रावधान करता है और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी वाद की सुनवाई केवल इसलिए समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि वाद की विषय-वस्तु में एक पक्ष का हित दौराने दावा दूसरे पक्ष को हस्तांतरित हो जाता है। ऐसा वाद उस व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध, जिस पर ऐसा हित हस्तांतरित हुआ है, न्यायालय की अनुमति से जारी रखा जा सकता है। लेकिन, यदि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो वाद मूल पक्ष के साथ जारी रखा जा सकता है और जिस व्यक्ति पर हित हस्तांतरित हुआ है वह बाध्य होगा और डिक्री का लाभ उठा सकता है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि ऐसा न हो कि उचित रूप से कार्यवाही में दिखाया गया है कि मूल पक्ष को अब कार्यवाही में कोई दिलचस्पी नहीं होने के कारण उसने सख्ती से वाद नहीं चलाया या प्रतिद्वंद्वी के साथ मिलीभगत की, जिसके परिणामस्वरूप उस पक्ष के प्रतिकूल निर्णय हुआ, जिस पर हित हस्तांतरित हुआ था। विधानमंडल ने नियम 3, 4 और 10 बनाते समय स्पष्ट भेद किया है।

नियम 3 और 4 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, यदि वाद करने का अधिकार जीवित रहता है और निर्धारित समय के भीतर मृत पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों को लाने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया जाता है, तो वाद स्वतः समाप्त हो जाता है और इस निरस्तीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया नियम 9 उसमें बताए गए आधारों पर निर्धारित की गई है। नियम 10 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, विधानमंडल ने उस व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने के लिए अदालत की अनुमति के लिए आवेदन करने में विफलता की स्थिति में ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है, जिस पर वाद के लंबित रहने के दौरान हित हस्तांतरित किया गया हो। विधानमंडल इस घटना के प्रति सचेत था और फिर भी यह निर्धारित नहीं किया है कि विफलता के कारण वाद खारिज हो जाएगा क्योंकि इसका उद्देश्य यह था कि कार्यवाही मूल पक्ष द्वारा या उसके खिलाफ जारी रहेगी, हालांकि वाद की विषय वस्तु में उसकी कोई रुचि नहीं रही।

संहिता के नियम 10, आदेश 22 के तहत, जब किसी वाद के लंबित रहने के दौरान हित का हस्तांतरण हुआ हो, तो अदालत की इजाजत से, वाद उन व्यक्तियों द्वारा या उनके खिलाफ जारी रखा जा सकता है, जिन पर ऐसा हित हस्तांतरित हुआ है और यह उस व्यक्ति को अधिकार देता है, जिसने किसी समनुदेशन या सृजन या हित के हस्तांतरण द्वारा वाद की

विषय वस्तु में रुचि अर्जित की है, वाद जारी रखने के लिए अनुमति के लिए अदालत में आवेदन करने के लिए अधिकार देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है। यदि कोई पक्ष अनुमति नहीं मांगता है, तो वह स्पष्ट जोखिम लेता है कि वादी द्वारा रिकॉर्ड पर वाद ठीक से संचालित नहीं किया जा सकता है, और फिर भी, जैसा कि (न्यायिक समिति के आधिपत्य द्वारा) मोती लाल बनाम करब-उद-दीन, (1898) 25 कैल.179 में बताया गया है कि वह वाद के परिणाम से बाध्य होगा, भले ही वह सुनवाई में प्रतिनिधित्व नहीं करता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि वाद नहीं था मूल पक्ष द्वारा ठीक से संचालन किया गया या उसने प्रतिद्वंद्वी के साथ मिलीभगत की। यह भी स्पष्ट है कि यदि वह व्यक्ति जिसने हस्तांतरण द्वारा हित अर्जित किया है, वाद को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति प्राप्त करता है, तो उसके हाथ में वाद कोई नया वाद नहीं है, क्योंकि, जैसा कि न्यायिक समिति के लॉर्ड किंग्सडाउन ने प्राणनाथ बनाम रूकिया बेगम, (1851-59) 7 एम.आई.ए. 323 में कहा था। केवल स्वामित्व के हस्तांतरण से वाद कारण लम्बा नहीं होता है। यह उसके कहने पर चलाया गया पुराना वाद है और वह उस चरण तक सभी कार्यवाहियों से बंधा हुआ है जब उसे कार्यवाही जारी रखने के लिए अनुमति मिल जाती है।

वाद के लंबित रहने के दौरान अनुमति मांगने या उस व्यक्ति को रिकॉर्ड पर लाने में विफलता का प्रभाव, जिस पर हित हस्तांतरित हुआ है, इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न निर्णयों में विचार का विषय था। श्रीमती सैला बाला दासी बनाम श्रीमती निर्मला सुंदरी दासी एवं अन्य, एआईआर (1958) सुप्रीम कोर्ट 394 के मामले में टी.एल. वेंकटराम अय्यर, जे. अपनी ओर से और एस.आर. की ओर से बताते हुए एवं दास, सी.जे. और ए.के. सरकार और विवियन बोस, जे.जे. यह कानून निर्धारित किया गया है कि दौराने दावा यदि किसी पक्ष के पक्ष में स्थानांतरण किया जाता है, तो इसका परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब दौराने दावा मूल अदालत में रिकॉर्ड पर लाए जाने हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया गया हो।

रिखू देव चेला बावा हरजुग दास बनाम सोम दास (मृतक) अपने चेला श्यामा दास, के माध्यम से एआईआर (1975) सुप्रीम कोर्ट 2159 के मामले में संहिता के आदेश 22 नियम 10 के अर्थ के भीतर किसी वाद के लंबित रहने के दौरान हित के हस्तांतरण का उसकी सुनवाई पर प्रभाव पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने पृष्ठ 2160 पर कानून निर्धारित किया है जो इस प्रकार है: -

"यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी वाद की सुनवाई को केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा

सकता है क्योंकि वाद की विषय वस्तु में एक पक्ष का हित दौराने दावा दूसरे पक्ष को हस्तांतरित हो गया है, लेकिन न्यायालय की अनुमति से हित प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस वाद को जारी रख सकता है। जब प्रतिनिधि क्षमता में किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ वाद लाया जाता है और प्रतिनिधि के हितों का हस्तांतरण होता है, तो जो नियम लागू किया जाना है वह आदेश 22, नियम 10 है न कि नियम 3 या 4, चाहे हस्तांतरण मृत्यु के परिणामस्वरूप हो या किसी अन्य कारण से। आदेश 22, नियम 10, मृत्यु द्वारा किसी पार्टी के हित के हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है; यह तब भी लागू होता है जब के मठ का प्रमुख या मंदिर का प्रबंधक अपने पद से इस्तीफा दे देता है या पद से हटा दिया जाता है। ऐसे मामले में मठ के प्रमुख या मंदिर के प्रबंधक के उत्तराधिकारी को इस नियम के तहत एक पक्ष के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है।"

किरण सिंह एवं अन्य बनाम चमन पासवान एवं अन्य, एआईआर (1954) एस.सी.340 के मामले में, सवाल उठाया गया था, जब एक न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अमान्य है और क्या ऐसी डिक्री के निष्पादन का निष्पादन के प्रक्रम पर विरोध किया जा सकता है, जो कि स्पष्ट रूप



से संहिता की धारा 47 के तहत आपत्ति लेना है। वेंकटराम अय्यर, जे. ने अपनी ओर से और बी.के. मुखर्जी, विवियन बोस, गुलाम हसन, जे.जे. की ओर से पृष्ठ 352 पर इस प्रकार अवलोकन किया:

"यह एक मौलिक सिद्धांत है जो अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिकार क्षेत्र के बिना किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अमान्य है, और इसकी अमान्यता तब स्थापित की जा सकती है जब भी और जहां भी इसे लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है, यहां तक कि निष्पादन के चरण में भी और यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी।"

इत्तियाविरा मथाई बनाम वर्की वर्की एवं अन्य, एआईआर (1964) एस.सी. 907 के मामले में, इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न विचाराधीन था, वह यह था कि क्या एक न्यायालय, जो वाद के पक्षों और उसके विषय पर अधिकार क्षेत्र रखता है, एक डिक्री पारित करता है। एक वाद जो समय से बाधित था, ऐसी डिक्री शून्यता के दायरे में आएगी और न्यायालय ने प्रश्न का उत्तर दिया नकारात्मक धारणा में है कि इस तरह के डिक्री को अमान्य नहीं माना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसे अवैध

डिक्री माना जा सकता है। कानून बनाते समय, न्यायालय ने पृष्ठ 910 पर इस प्रकार कहा: -

"यदि वाद मियाद बाहर था और फिर भी, अदालत ने उस पर फैसला सुनाया, तो अदालत एक अवैधता कर रही होगी और इसलिए पीड़ित पक्ष इसके खिलाफ अपील करके डिक्री को रद्द कराने का हकदार होगा। लेकिन यह अच्छी तरह से तय है कि वाद की विषय-वस्तु और उसके पक्षों पर क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालत, हालांकि सही निर्णय लेने के लिए बाध्य है, गलत निर्णय ले सकती है; और भले ही उसने गलत निर्णय लिया हो, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसे करने का उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। न्यायालय के पास वाद के पक्षों एवं विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार था और इसलिए, केवल इसलिए कि इसने वाद में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को तय करने में त्रुटि की, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया है। जैसा कि अक्सर कहा गया है, अदालतों को सही या गलत का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है और भले ही वे गलत फैसला करते हैं, उनके द्वारा दिए गए आदेशों को अमान्य नहीं माना जा सकता है।"

फिर, वासुदेव धनजीभाई मोदी बनाम राजभट्ट अब्दुल रहमान एवं अन्य, एआईआर (1970) एससी 1475 के मामले में, न्यायालय एक डिक्री की निष्पादन क्षमता के संबंध में संहिता की धारा 47 के तहत आपत्ति की गुंजाइश पर विचार कर रहा था और यह निर्धारित किया गया था केवल ऐसी डिक्री ही आपत्ति का विषय हो सकती है जो आमन्य हो, न कि ऐसी डिक्री जो कानून या तथ्यों के आधार पर गलत हो। जे.सी. शाह, जे. अपनी ओर से और के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग़ोवर, जे.जे. की ओर से बोलते हुए पृष्ठ 1476-77 पर कानून बनाया जो इस प्रकार है:-

"किसी डिक्री को क्रियान्वित करने वाला न्यायालय पार्टियों या उनके प्रतिनिधियों के बीच डिक्री के पीछे नहीं जा सकता; उसे डिक्री को उसके तत्व (Tenor) के अनुसार लेना चाहिए, और किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं कर सकता कि डिक्री कानून या तथ्यों के आधार पर गलत थी। जब तक इसे अपील या पुनरीक्षण में रद्द नहीं किया जाता। एक डिक्री गलत होने पर भी पार्टियों के बीच बाध्यकारी होती है जब एक डिक्री जो अमान्य है, उदाहरण के लिए, जहां इसे किसी ऐसे व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लिए बिना पारित किया जाता है जो डिक्री की तारीख पर

मर चुका था, या एक प्रमाण पत्र के बिना एक सत्तारूढ़ राजकुमार के खिलाफ निष्पादित किया जाना चाहता है, तो निष्पादन की कार्यवाही में उस संबंध में आपत्ति उठाई जा सकती है। फिर, जब डिक्री किसी ऐसे न्यायालय द्वारा की जाती है जिसके पास इसे बनाने का कोई अंतर्निहित क्षेत्राधिकार नहीं है, तो निष्पादन कार्यवाही में इसकी वैधता पर आपत्ति उठाई जा सकती है, यदि आपत्ति रिकॉर्ड पर दिखाई देती है: जहां डिक्री पारित करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं देती है और वाद में उठाए गए और तय किए गए प्रश्नों की जांच की आवश्यकता होती है या जो हो सकते थे लेकिन उठाया नहीं गया है, निष्पादन न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार की अभाव के आधार पर भी डिक्री की वैधता के बारे में आपत्ति पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।"

एवरेस्ट कोल कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, [1978] 1 एससीसी 12 के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि रिसीवर पर वाद दायर करने की अनुमति वाद दायर करने के बाद भी दी जा सकती है और माना गया कि अनुमति प्राप्त न करने की निश्चिन्ता ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र या कार्यवाही के कारण पर निर्भर नहीं करता है,

लेकिन यह परिधीय है। यह भी माना गया कि यदि ऐसी अनुमति के बिना वाद चलाने पर डिक्री प्राप्त हो जाती है, तो उसे रद्द कर दिया जा सकता है। इन टिप्पणियों का मतलब यह नहीं है कि डिक्री अमान्य है। दूसरी ओर, पृष्ठ 15 पर न्यायालय की टिप्पणी है कि "न्यायालय की अनुमति के बिना उसके कब्जे में कोई भी मुकदमेबाजी में गड़बड़ी उसके अधिकार की अवमानना है और इस क्षेत्राधिकार में न्यायालय की अवमानना की कीमत पूरी कार्यवाही की शून्यता हो सकती है "इस दृष्टिकोण को समर्थन देती है, और ऐसी डिक्री रद्द करने योग्य है लेकिन शून्य नहीं है।

हाजी एसके.सुभान बनाम माधोराव, एआईआर (1962) एस.सी. 1230 के मामले में, इस न्यायालय के विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या कोई निष्पादन न्यायालय इस आधार पर किसी डिक्री को निष्पादित करने से इनकार कर सकता है कि वह निष्पादन योग्य नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून में बदलाव के चलते एम.पी. मालिकाना अधिकार (संपदा, महल, अलग की गई भूमि) अधिनियम, 1950 का उन्मूलन बनाया गया और उसी की अनदेखी में एक डिक्री पारित की गई थी। प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए, गौट ने पृष्ठ 1287 पर इस प्रकार टिप्पणी की:-

"यह तर्क कि निष्पादन न्यायालय डिक्री पर सवाल नहीं उठा सकता है और इसे यथास्थिति में निष्पादित करना

होगा, सही है, लेकिन इस सिद्धांत का वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई प्रभाव नहीं है। अपीलकर्ता की आपत्ति इसकी अमान्यता के संबंध में नहीं है बल्कि डिक्री या डिक्री के गलत होने के संबंध में है। उनकी आपत्ति अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव पर आधारित है, जिसने प्रतिवादी को उसके मालिकाना अधिकारों से वंचित कर दिया है, जिसमें वाद में भूमि पर कब्जा वापस पाने का अधिकार भी शामिल है और जिसके प्रावधानों के तहत प्रतिवादी ने इस पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि निष्पादन न्यायालय निष्पादित करने से इनकार कर सकता है डिक्री में कहा गया है कि कानून में बदलाव और उसके प्रभाव के कारण यह निष्पाद्य हो गया है।"

विद्या सागर बनाम श्रीमती सुदेश कुमारी एवं अन्य, एआईआर (1975) एस.सी. 2295, के मामले में। संहिता की धारा 47 के तहत इस आशय की आपत्ति ली गई थी कि पारित डिक्री यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के पारित होने के बाद निष्पादन में असमर्थ है और आपत्ति को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और जब मामला इस न्यायालय में लाया गया था, तो आदेश को बरकरार रखा गया

था कि डिक्री राज्य विधानमंडल द्वारा कानून की घोषणा के बाद निष्पादन में असमर्थ थी।

'शून्य और शून्यकरणीय' पद अनेक बार इंग्लिश न्यायालयों के समक्ष विचार का विषय रहे हैं। दुरयप्पा बनाम फर्नांडो एवं अन्य, (1967) 2 ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट 152 के मामले में, मंत्री द्वारा नगरपालिका परिषद के विघटन को चुनौती दी गई थी। प्रिवी काउंसिल के समक्ष यह प्रश्न उठा था कि क्या कोई तीसरा पक्ष इस तरह के निर्णय को चुनौती दे सकता है। यह माना गया कि यदि निर्णय पूरी तरह से अमान्य है, तो इसे कोई भी, कहीं भी चुनौती दे सकता है। न्यायालय ने पृष्ठ 158 पर इस प्रकार टिप्पणी की:-

"उत्तर अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मंत्री का आदेश पूरी तरह से अमान्य था या क्या यह केवल परिषद के चुनाव में रद्द करने योग्य आदेश था। यदि पूर्व, तो इसका पालन करना होगा कि परिषद अभी भी कार्यालय में है और यदि, परिषद के संचालन में वैध हित रखने वाला कोई भी पार्षद, रेटपेयर या अन्य व्यक्ति इस मुद्दे पर विचार करना चाहता है, तो वे अदालत से यह घोषित करने के लिए कहने के हकदार हैं कि परिषद अभी भी विधिवत निर्वाचित परिषद है, जिसके पास नगरपालिका अध्यादेश द्वारा" प्रदत्त सभी शक्तियां और कर्तव्य हैं।

इन री मैकसी (एक नाबालिग) (1985) 1 अपील मामले 528, के मामले में दहाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मार्शलसी केस में लॉर्ड कोक के आदेश (dictum) का पालन किया। उक्त निर्णय के एक अंश को उद्धृत करते हुए जो 1613 में दिया गया था, यह निर्धारित किया गया था कि जहां पूरी कार्यवाही कोरम नाॅन ज्युडिस है जिसका अर्थ है शुरुआत से ही शून्य, कार्रवाई सिद्धांत या प्रक्रिया की परवाह किए बिना की जाएगी। न्यायालय ने पृष्ठ 536 पर इस प्रकार कहा:-

बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम के दो चरम सीमाओं पर विचार करें। 1613 में लॉर्ड कोक के लिए क्षेत्राधिकार का एक ही मतलब था जब उन्होंने (1613) 10 Co. Rep. 68 बी, मामले में पृष्ठ 76 ए पर कहा था:

"जब किसी अदालत के पास मामले का क्षेत्राधिकार होता है, और, विपरीत क्रम में या गलत तरीके से आगे बढ़ता है, तो वहां वाद करने वाला पक्ष, या अदालत का अधिकारी या मंत्री जो अदालत की precept या प्रक्रिया को निष्पादित करता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब अदालत के पास मामले का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वहां पूरी कार्यवाही कोरम नाॅन ज्युडिस (coram non



judice) हैं, और सिद्धांत या प्रक्रिया की परवाह किए बिना कार्रवाई उनके खिलाफ होगी।"

उस मामले में मार्शलस की अदालत ने क्षेत्राधिकार के बिना काम किया, क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार राजा के घर के सदस्यों तक सीमित था, उसने दो नागरिकों के बीच एक वाद पर विचार किया, जिनमें से कोई भी राजा के घर का सदस्य नहीं था। उन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप मार्शल प्रक्रिया द्वारा गिरफ्तार किया गया पक्ष, अन्य बातों के अलावा, "प्रक्रिया के निष्पादन का निर्देश देने वाले मार्शल" के विरुद्ध झूठे कारावास की कार्रवाई कर सकता है। यह कई बाद के मामलों में दर्शाए गए सिद्धांत के अनुप्रयोग का एक प्रारंभिक और शायद सबसे उद्धृत उदाहरण है, जहां यह सवाल कि क्या किसी अदालत या सीमित क्षेत्राधिकार के अन्य न्यायाधिकरण ने क्षेत्राधिकार के बिना कार्य किया है (कोरम नॉन ज्यूडिस) इस पर विचार करके निर्धारित किया जा सकता है कि क्या कार्यवाही की शुरुआत में अदालत के पास कार्यवाही पर विचार करने का क्षेत्राधिकार था। लॉर्ड कोक के वाक्यांश "कारण के क्षेत्राधिकार" में बहुत कुछ निहित है।

एक अन्य निर्णय में, लोक अभियोजन निदेशक बनाम प्रमुख, (1959) अपील मामले 83 के मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक आपराधिक मामले में पारित बरी के फैसले के खिलाफ अपील में राज्य के

सचिव द्वारा पारित आदेश की वैधता पर विचार कर रहा था। आपराधिक अपील की अदालत ने इस आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर दिया कि सचिव का उपरोक्त आदेश अमान्य था और आपराधिक अपील की अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पृष्ठ 111 पर इस प्रकार टिप्पणी की: -

"मुझे ऐसा लगता है कि यह विवाद शून्य या शून्यकरणीय के पूरे प्रश्न को उठाता है: यदि मूल आदेश शून्य था, तो यह कानून में अमान्य होगा। इसे रद्द करने के लिए किसी आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह स्वचालित रूप से शून्य होगा। निरंतरता के आदेश भी शून्य होंगे, क्योंकि आप शून्यता जारी नहीं रख सकते। मिस हैंडरसन का लाइसेंस शून्य होगा। इसी तरह 1913 के अधिनियम की धारा 64 के तहत उनकी संपत्ति के साथ सभी लेनदेन भी शून्य होंगे। इनमें से कोई आदेश साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे। मुझे लगता है कि राज्य सचिव उन सभी 10 वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके दौरान उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था, क्योंकि यह सब उनके लापरवाह कृत्य से उत्पन्न

हुआ कहा जा सकता है; धारा 16 मानसिक उपचार अधिनियम, 1930 देखें।

लेकिन यदि मूल आदेश ही शून्यकरणीय था, तो स्वचालित रूप से शून्य नहीं होगा इससे बचने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इसे रद्द करने के लिए प्रमाणन (certiorari) के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करना होगा।"

इस प्रश्न की जांच अपील न्यायालय द्वारा आर. वी. पैडिंगटन वैल्यूएशन ऑफिसर और अन्य, एक्सपार्ट पीची प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, (1965) 2 ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट 836 के मामले में की गई थी, जहां मूल्यांकन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह पूरी तरह से शून्य था. इन तथ्यों पर, लॉर्ड डेनिंग, एम.आर. ने पृष्ठ 841 पर देखते हुए कानून इस प्रकार निर्धारित किया: -

"दो प्रकार की अमान्यता के बीच अंतर करना आवश्यक है। एक प्रकार वह है जहां अमान्यता इतनी गंभीर है कि सूची पूरी तरह से शून्य है। ऐसी स्थिति में इसे रद्द करने के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से अमान्य और शून्य है। दूसरा प्रकार तब होता है जब अमान्यता सूची को पूरी तरह से शून्य नहीं बनाती है,

बल्कि केवल रद्द करने योग्य बनाती है। उस स्थिति में यह तब तक कायम रहती है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में मूल्यांकन सूची न तो शून्य है और न ही कभी रद्द की गई है। अधिक से अधिक प्रथम प्रत्यर्थी ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करते हुए-उस क्षेत्राधिकार का गलत से प्रयोग किया है। यह सूची को शून्य नहीं बल्कि रद्द करने योग्य बनाता है। यह तब तक अच्छा रहता है जब तक कि इसे रद्द नहीं कर दिया जाता है।"

डी स्मिथ, वुल्फ और जोवेल ने अपने ग्रंथ ज्यूडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, पांचवें संस्करण, पैराग्राफ 5-044 में शून्य और शून्यकरणीय की अवधारणा को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया है:

"शून्य और शून्य कृत्यों (अमान्य घोषित होने तक अमान्य और वैध) के सरल द्वंद्व के पीछे कष्टदायी जटिलता की शब्दावली और वैचारिक समस्याएं छिपी हैं। समस्याएं इस आधार पर उत्पन्न हुईं कि यदि कोई कार्य, आदेश या निर्णय अधिकार के दायरे से बाहर है क्षेत्राधिकार के बाहर, इसे अमान्य, या शून्य और अवैध कहा गया था। यदि यह अधिकार के अंदर है, तो यह निश्चित रूप से वैध था। यदि

यह अधिकार या क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के भीतर की गई किसी त्रुटि से दोषपूर्ण है, तो इसे आमतौर पर शून्यकरणीय; कहा जाता था। अर्थात्, अपील पर रद्द किए जाने तक या अतीत में रिकॉर्ड के आधार पर कानून की त्रुटि के लिए सर्टिओरीरी द्वारा रद्द किए जाने तक वैध है।"

क्लाइव लुईस ने अपनी कृति ज्यूडिशियल रेमेडीज़ इन पब्लिक लॉ में पृष्ठ 131 पर "शून्य और शून्यकरणीय" अभिव्यक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की है: -

"किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती प्रत्यक्ष कार्रवाई या संपार्श्विक या अप्रत्यक्ष चुनौती के माध्यम से हो सकती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई वह है जहां कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अमान्यता स्थापित करना है। यह आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन के माध्यम से या अपील या समीक्षा के लिए किसी वैधानिक तंत्र के उपयोग के माध्यम से होगा। जब कुछ अन्य कार्यवाहियों के दौरान अमान्यता को उठाया जाता है, तो संपार्श्विक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसका उद्देश्य अमान्यता स्थापित करना नहीं है, बल्कि जहाँ वैधता के प्रश्न प्रासंगिक हो जाते हैं।"

इस प्रकार 'शून्य और शून्यकरणीय' अभिव्यक्तियाँ असंख्य अवसरों पर न्यायालयों द्वारा विचार का विषय रही हैं। अभिव्यक्ति "शून्य" के कई पहलू हैं। एक प्रकार के शून्य कार्य, लेनदेन, डिक्री वे हैं जो पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना हैं, शुरू से ही शून्य हैं और इससे बचने के लिए किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है, कानून इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और यह संपार्श्विक कार्यवाही में या अन्यथा उपेक्षा की जा सकती है। अन्य प्रकार का शून्य कार्य, उदाहरण के लिए, किसी नेक्सट फ्रेंड द्वारा प्रतिनिधित्व किए बिना किसी नाबालिग के खिलाफ लेनदेन हो सकता है। ऐसा लेनदेन पूरी दुनिया के खिलाफ अच्छा लेनदेन है। जहां तक नाबालिग का प्रश्न है, यदि वह इससे बचने का निर्णय लेता है और उचित कार्यवाही का सहारा लेकर इसे टालने में सफल हो जाता है तो लेनदेन शुरू से ही शून्य हो जाता है। एक अन्य प्रकार का शून्य कार्य हो सकता है जो शून्य नहीं है लेकिन उससे बचने के लिए एक घोषणा करनी होगी शून्यकरणीय कार्य वह है जो एक अच्छा कार्य है जब तक कि उसे टाला न जाए, उदाहरण के लिए, यदि यह घोषणा करने के लिए वाद दायर किया जाता है कि कोई दस्तावेज़ धोखाधड़ीपूर्ण और/या जाली और मनगढ़ंत है, तो यह शून्यकरणीय है क्योंकि मामलों की स्पष्ट स्थिति वास्तविक मामलों की स्थिति है और एक जो पक्ष अन्यथा आरोप लगाता है वह इसे साबित करने के लिए बाध्य है। यदि यह साबित हो जाता है कि दस्तावेज़ जाली और

मनगदंत है और इस आशय की घोषणा दी जाती है तो लेनदेन शुरू से ही अमान्य हो जाता है। कोई शून्यकरणीय लेन-देन हो सकता है जिसे अलग रखा जाना आवश्यक है और इसे उसी दिन से टाला जाना चाहिए जिस दिन इसे अलग रखा गया है, न कि उससे किसी दिन पहले। ऐसे मामलों में, जहां किसी दस्तावेज़ का कानूनी प्रभाव उसे रद्द किए बिना नहीं हटाया जा सकता है, इसे शून्य नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से रद्द करने योग्य होगा।

संहिता की धारा 47 के तहत, जिस वाद में डिक्री पारित की गई थी, उसके पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित सभी प्रश्न डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए, न कि डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा एवं न ही किसी पृथक वाद के जरिये धारा 47 के तहत न्यायालय की शक्तियाँ उसकी अपील, पुनरीक्षण या समीक्षा की शक्तियों से काफी भिन्न और बहुत संकीर्ण हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय कानून के तहत न केवल सशक्त है, बल्कि कानून के सवालों के अलावा ट्रायल कोर्ट की तरह तथ्यों के सवालों पर भी विचार करने के लिए बाध्य है। संहिता की धारा 100 जैसे विभिन्न कानूनों के तहत द्वितीय अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ, जैसा कि 1.2.1977 से प्रभावी 1976 के केंद्रीय अधिनियम 104 द्वारा इसके संशोधन से पहले थीं, का प्रयोग केवल कानून के प्रश्न पर किया जा सकता

था। उपरोक्त केंद्रीय अधिनियम द्वारा संशोधित और प्रतिस्थापित संहिता की धारा 100 के समान कानूनों के तहत शक्तियों को और अधिक सीमित कर दिया गया है क्योंकि अब ऐसी अपील में केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी मामले में कानून का पर्याप्त प्रश्न उठता है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि ऐसा प्रश्न सामान्य सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए और इसके लिए इस न्यायालय के निर्णय की आवश्यकता होती है। संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आदेश विधिक अशक्तता से ग्रस्त है या कानून का पर्याप्त प्रश्न उठता है, बल्कि ऐसी त्रुटि को क्षेत्राधिकार की त्रुटि के दोष से ग्रस्त होना चाहिए। बेशक, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण शक्तियां और इसी तरह समान कानूनों में पूरी तरह से अलग स्तर पर और बहुत व्यापक हैं क्योंकि वहां अदालत आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य और निचली अदालत की कार्यवाही की नियमितता में जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में पुनरीक्षण न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय की तरह तथ्यों के प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य है, बल्कि न्यायालय के पास उचित मामलों में उस पर विचार करने का विवेक है जब भी यह समीचीन पाया जाता है



और प्रत्येक में नहीं। निःसंदेह, विवेक का अर्थ न्यायिक विवेक है, न कि किसी न्यायाधीश की सनक या मनमर्जी। समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक यह न दिखाया जाए कि समीक्षा किए जाने वाले आदेश में रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि है।

संहिता की धारा 47 के तहत शक्तियों का प्रयोग सूक्ष्म है और एक बहुत ही संकीर्ण निरीक्षण क्षेत्र में निहित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निष्पादन न्यायालय डिक्री की निष्पादन क्षमता पर संहिता की धारा 47 के तहत आपत्ति की अनुमति दे सकता है यदि यह पाया जाता है कि डिक्री प्रारंभिक रूप से शून्य और अशक्त है, इस आधार के अलावा कि डिक्री कानून के तहत निष्पादन में सक्षम नहीं है। क्योंकि इसे कानून के ऐसे प्रावधान की अनदेखी में पारित किया गया था या इसके पारित होने के बाद किसी कानून को अक्षम्य बनाकर कानून प्रख्यापित किया गया था। मौजूदा मामले में, कॉलेज के शासी निकाय के खिलाफ डिक्री पारित की गई थी, जो विश्वविद्यालय के खिलाफ वाद जारी रखने और उसे पक्षकार बनाने के लिए अदालत से अनुमति मांगे बिना प्रतिवादी थी। इस तरह की चूक डिक्री को शुरू से ही रद्द नहीं कर देगी ताकि संहिता की धारा 47 लागू हो और निष्पादन को खारिज कर दिया जाए। किसी डिक्री की वैधता या अन्यथा को उचित रूप से वाद दायर करके या कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय से इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि मूल

प्रतिवादी ने उपस्थिति के बाद वाद की कार्यवाही से खुद को अनुपस्थित कर लिया क्योंकि उसे विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विवाद का या जानबूझकर कार्यवाही में रुचि नहीं ली या विरोधी के साथ मिलीभगत की अथवा कानून के तहत स्वीकार्य किसी अन्य आधार पर।

अब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले, इसमें शामिल बिंदु की बेहतर सराहना के लिए, संहिता के आदेश 22 नियम 10 के प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार चलता है: -

"10. वाद के लंबित रहने के दौरान किसी हित के समनुदेशन, सृजन या न्यागमन की अन्य दशाओं में, वाद न्यायालय की इजाजत से उस व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखा जा सकेगा जिसको ऐसा हित प्राप्त या न्यागत हुआ है।

(2) किसी डिक्री की अपील के लंबित रहने के दौरान उस डिक्री की कुर्की के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसा हित है जिससे वह व्यक्ति जिसने ऐसी कुर्की कराई थी, उपनियम (1) का फायदा उठाने का हकदार हो गया है।"

ऊपर उल्लिखित नियम 10 की सरल भाषा यह नहीं सुझाती है कि अनुमति केवल उस व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है जिस पर हित का समनुदेशन हुआ है। इसमें बस इतना कहा गया है कि वाद उस व्यक्ति द्वारा जारी रखा जा सकता है जिस पर ऐसा हित हस्तांतरित हुआ है और यह उस मामले में लागू होता है जहां वादी का हित हस्तांतरित हुआ है। इसी तरह, ऐसे मामले में जहां प्रतिवादी का हित हस्तांतरित हो गया है, वाद ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी रखा जा सकता है, जिस पर हित का समनुदेशन हुआ है, लेकिन किसी भी स्थिति में, वाद के लंबन काल में उन व्यक्तियों के खिलाफ वाद जारी रखा जा सकता है, जिन पर ब्याज हस्तांतरित हुआ है। अदालत की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि यह निर्धारित किया जाता है कि अनुमति केवल उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिस पर वाद के लंबित रहने के दौरान पक्षकार का हित हस्तांतरित हुआ है, तो बेतुके परिणाम हो सकते हैं क्योंकि ऐसा पक्ष मुकदमेबाजी के बारे में नहीं जानता होगा और परिणामस्वरूप इसके लिए संभव नहीं होगा कि वह अनुमति के लिए आवेदन कर सके और यदि उस पर कोई कर्तव्य डाला जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुमति के लिए आवेदन न करने की स्थिति में भी वह डिक्री से बंधा होगा। विवेक के एक नियम के रूप में, यदि हस्तांतरण का तथ्य उसकी जानकारी में था तो अनुमति के लिए आवेदन करना वादी का प्रारंभिक कर्तव्य है। उचित परिश्रम से उसे

ज्ञात किया जा सकता था। वह व्यक्ति जिस पर हित हस्तांतरित हो गया है, वह भी ऐसी अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है ताकि उसके हित को मूल पक्ष के रूप में उचित रूप से दर्शाया जा सके, यदि मूल पक्षकार, सामान्य तौर पर, जो स्वाभाविक है, किसी अन्य व्यक्ति को हित हस्तांतरित होने के कारण विवाद की विषय वस्तु में उसका हित समाप्त हो गया हो या दूसरे पक्ष के साथ मिलीभगत करके, उसमें रुचि नहीं लेता। यदि श्री मिश्रा की दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो जिस पक्ष पर हित हस्तांतरित हो गया है, वह अनुमति के लिए आवेदन करने में असफल होने पर, इस आधार पर उचित रूप से गठित वाद दायर करके डिक्री की शुद्धता को चुनौती देने से वंचित हो जाएगा कि मूल पक्ष ने वाद की विषयवस्तु में हित खो देने के कारण उचित रूप से वाद नहीं चलाया या वाद का बचाव करना या, ऐसा करते हुए, विरोधी के साथ मिलीभगत कर ली। हमारे विचार में, कोई अन्य पक्ष भी अनुमति की मांग कर सकता है, उदाहरण के लिए, जहां वादी ने विभाजन के लिए वाद दायर किया और इसके लंबित रहने के दौरान उसने मिताक्षरा सहदायिकता में अपना अविभाजित हित प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी के पक्ष में दान कर दिया, उस स्थिति में प्रतिवादी पर मूल वादी का हित स्थानांतरित होने से उसके पास वाद चलाने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। लेकिन यदि कोई अन्य सह-हिस्सेदार है जो वादी का समर्थन कर रहा है, तो उसके पास खुद को शामिल करके वाद

जारी रखने के लिए कार्रवाई का कारण हो सकता है इसे वादी की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विभाजन के वाद में प्रत्येक प्रतिवादी वादी है, बशर्ते उसके पास विभाजन की मांग करने के लिए कार्रवाई का कारण हो। इस प्रकार, हम अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की इस दलील में कोई सार नहीं पाते हैं और मानते हैं कि अनुमति के लिए प्रार्थना न केवल उस व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर हित हस्तांतरित हुआ है, बल्कि वादी या किसी अन्य कोई रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है।

इस प्रकार, पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर, हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 47 के तहत आपत्ति की अनुमति देना उचित नहीं था।

परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया जाता है। मामले की परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि पक्षकार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

वी.एस.एस.

अपील की अनुमति

नोट- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूजा धानिया (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।